[Prof. P. J. Kurian]

World Health Organisation. The toxic effects of these chemicals on the biological syetem are too frightening to be described here.

Unfortunately, there is no satisfactory regulatory mechnism existing in this country. Therefore, in view of the serious health hazard being caused by the excessive use of pesticides, I would request the Government to take immediate steps to effectively regulate the use of toxic agro-chemicals in the country.

**(iii) Demand for a Railway line between Sahajawan and Dorighat.**

**श्री महावीर प्रसाद** (बांसगांव) : मान्यवर, मैं आपका ध्यान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव जो शदियों से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, में रेलवे लाइन के निर्माण के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ। श्रीमन्, यह क्षेत्र सामाजिक आर्थिक एंव शैक्षणिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी उद्योग नहीं है। मैं यदि औद्योगिकरण के प्रति राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं तो उत्तर में यही मिलता है कि उस क्षेत्र में रेलवे लाइन नहीं है। इस सार्वजनिक निजी, सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्रों में कोई भी उद्योग नहीं लग सकता है। यही नहीं जहां तक मेरी जानकारी है कि भारत वर्ष में एक मात्र तहसील बांसगांव है जहां पर एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं है। इससे बढ़कर मेरे लिए तथा उस क्षेत्र की जनता के लिए दूर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। इस संबन्ध में मैंने कई बार इस सदन में आवाज उठाई है लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इतना ही नहीं सहजनवां से दोहरीघाट तक रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में तीन-तीन बार सर्वेक्षण हो चुका है तथा संकेत पत्थर भी लग चुके हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद कहा जा रहा है कि दस प्रतिशत आर्थिक प्रतिफल नहीं आ रहा है इसलिए इस योजना पर विचार करना अभी संभव नहीं है। अत: आपके माध्यम से पुन: निवेदन है कि मई सन् 1980 की जो राष्ट्रीय परिवहन नीति बनी है उसको आधार मानते हुए तथा आर्थिक प्रतिफल को त्यागते हुए क्षेत्रीय पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सयजनवां से दोहरीघाट तक रेलवे लाइन बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए ताकि मेरी तहसील की जानता भी रेलवे लाइन का दर्शन कर सके।

**(iv) Staff transfer Police in I.O.C**

SHRI BHEEKHABHAI (Banswara) : It is a matter of great surprise that though the Refineries Division of Indian Oil Corporation was established in October 1958, i.e. over a quarter of century ago, they have not yet framed any regular and clear cut transfer policy. The transfers were carlier effected mostly for Technical Officers, when the actual needs were felt. But, for the last three to four years the transfers in Refineries Division are being effected in a big way though each transfer costs the Management Rs. 10,000 to Rs. 20,000 due to its liberal transfer policy.

Another paradoxical situation is that though the staff members/workmen are also liable to transferred to other units, they are never moved from one station to other station. It is suggested that to avoid harassment and hardships, the following action be taken :—

I. No movement of officers should take place till a broad, enlightened and clear transfer policy is framed by the Corporation in consulation with recognised Unions and Officers' Association.